national organisations. And I am sorry, Sir—I have to share with the hon. House—in this field we do not have very many people to organise such kind of things on the international scale. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Mr, Minister, if you cast your enquiring eye on them, it would be a good thing, and if you promise this much they will be satisfied.

'SHRI BUTA SlNGH: I have asked them to send specific complaints.

MR. CHAIRMAN: They have already made many allegations. Just have a look into them.

SHRI BUTA SINGH: Yes.

SHRl J. K. JAIN: The IOC is an international body. If the Boeing company appoints Mr. Suresh Kalmadi as an agent, how can the Government of India come into the picture? The IOC has appointed Mr. Prahlad Bajaj.

MR. CHAIRMAN: Who is this person? I would like to know. That is a sufficient assurance.

National book policy

*85. SHRI. SHRIKANT VERMA: f
SHRI J. p. GOYAL:

Will the Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state:

<a) whether it is a fact that Government had set up a. Committee to prepare the draft of a National Book Policy;

(b) whether the said draft has since been prepared;

(c) if so, what are tbe salient features thereof; and

(d) if the reply to part (b) above be in the negative, by when a National Book Policy is likely to be finalised?

*The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shrikant Verma.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir. In September 1983 the National Book Development Council was reconstituted by the Government for the development of the Indian Book Industry and one of the Council's functions according to the Resolution of Government of India is to draft a National Book Policy which might represent a harmonious blend of the interests of the readers.

(b) and (c) No, Sir.

(d) The Council has held two meetings so far. At its second meeting held in April 1984, there was a general discussion on the need for a National Book Policy to promote bootemindedness and develop book industry in the country. This discussion covered inter-related issues concerning book production, problem of finance, marketing, distribution of books supported by a strong library movement. The Council will take up this further in its subsequent meetings in conformity with the functions entrusted to it.

श्री श्रीकांत वर्मा : सभापति महोदय, कोई भी देश हो बिना पुस्तक नीति के अपने साहित्य, शिक्षा का विकास नहीं कर सकता। इतने वर्ष हो गये, बड़े दुख की बात है कि सरकार के पास कोई राष्ट्रीय पुस्तक नीति नहीं है। उसके पास कौंसिल्स बहुत-सी हैं, परिषदें बहुत-सी हैं और बहुत-सी गोष्ठियाँ हैं लेकिन अब तक उनके विचार-विमर्श से कोई निष्कर्ष पर न तो शिक्षाविद् पहुंच सके हैं कि क्या इसकी पुस्तक नीति है और न प्रकाशक समझ सके हैं कि क्या पुस्तक का मूल्य होना चाहिये, गरीब देश में कितने दाम पर वह उपलब्ध होनी चाहिये छात्रों को और कौन-सा साहित्य छात्रों तक पहुंचना चाहिये, कौन-सा नहीं पहुंचना चाहिये ? इस पर कोई विचार-विमर्श अब तक नहीं

हुआ। शिक्षा मंत्री महोदय कम से कम एक आश्वासन दे सकते थे कि आज नहीं तो कल इस तरह की नीति हम तैयार करेंगे जैसाकि मैंने अपने प्रश्न "डी" में पूछा है। लेकिन इस पर भी उसका स्पष्ट उत्तर नहीं है। मैं उन से पूछना चाहूंगा कि क्या भविष्य में कोई भी, किसी भी तरह की पुस्तक नीति के बारे में विचार-विमर्श करने के लिये वह कोई परिसंवाद, बुलायेंगे शिक्षाविदों का, पुस्तक प्रकाशकों और लेखकों का, या ऐसे ही बिना किसी नीति के पुस्तक प्रकाशन उद्योग को चलने देंगे ?

SHRI P. K. THUNGON: Six as I said in the main text of my reply, *the* National Book Development Conucil looks after the framing of a National Book Policy also. With reference to book promotion, besides framing of a Book Policy, there are certain other functions which are entrusted to the National Book Development Council. Now, in its second meeting it has already discussed about this very important point and in the third meeting they are again going to discuss it. I can assure the hon. Member that we will request the Council if not by themselfres at least a group may be constituted so that they can go into the details quickly and a recommendation can be - evolved.

श्री श्रीकांत वर्मा : सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री सभापति : यह सवाल तो तीन-चार बार हो चुका है।

श्री श्रीकांत वर्मा : जी हां, हो चुका है। श्रीमन्, यह जो नेशनल बुक डेवलपमेंट बोर्ड है यह एक बोगस बाडी है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय इस तरह के बोगस काम बहुत करता है और बोगस लोगों को पेट्रोनेज देता है. . . (**व्यवधान**)।

श्री सभापति : मैं तो समझता था कि खाली स्पोर्ट्स की टिकटों में ही ऐसा होता है।

श्री श्रीकांत वर्मा : श्रीमन्, अगर आप नेशनल बुक डेवलपमेंट बोर्ड के मेम्बरों की लिस्ट को देखें, वह लिस्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसे मेम्बर मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिन्दगी में एक भी किताब नहीं पढ़ी होगी। ऐसे लोग बोर्ड के मेम्बर हैं और वे पुस्तकों की पालिसी बनाते हैं। ऐसी स्थिति में देश में किस तरह की पुस्तकें प्रकाशित होंगी, उनका क्या मूल्य होगा और किस तरह से ज्ञान का विकास होगा, यह आप जान सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ हो चुका है वह तो हो चुका है। अब आप आगे के लिये एक पुस्तक बोर्ड का गठन करें। उसमें आप ठीक-ठीक लोगों को रखें ताकि ठीक-ठीक नीति का विकास हो। उनसे मैं प्रश्न क्या पूछूं ?

श्री सभापति : आप तो अपनी बात का इजहार कर रहे हैं।

श्री श्रीकांत वर्मा : मैं उनसे क्या प्रश्न पूछूं क्योंकि वे कह रहे है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Sir, it happens in every field.

SHRI SHRIKANT VERMA: Sir, what question I should ask the Minister. No proper reply is forthcoming from him.

SHRI P. K. THUNGON: Sir, I would like to state that there are 34 members. Sir, I request the hon. Member to be patient. Even at this age he is very impatient.

MR. CHAIRMAN: Appointing the Committee Members who have not read even one book.

SHRI P. K. THUNGON: Sir, that can be identified after I read out the name$_s$ of the Committee Members.

(1) Shri Krishna Kripalani—Chairman

(2) Dr. Miss Kala Thairani—Member

(3) Shri Kireet Joshi—Member

(4) Shri Manmohan Singh—Member

(5) Shri Ravi Sawhney—Member

(6) Dr. Loknath Bhattarchrya—Member

(7) Dr. P. L. Malhotra—Member

(8) Shri Y. R. Chadha—Member

(9) Shri Indra Nath Choudhary

(10) Shri Ashin Das Gupta-Member

MR. CHAIRMAN: Just a minute. Mr. Verma, can you identify the person from the above list who has not read even one book?

SHU P. K. THUNGON: There are representatives from the newspaper, book publishes, book industry and all walks of life. Should I give the address also, Sir?

MR. CHAIRMAN: I heard the names and I know some of them. आप तो मुबालका जरा ज्यादा कर रहे हैं।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : हमारे माननीय मेम्बर साहब ने जो सवाल किया है उसके विषय में एक बात कहना चाहती हूं कि हम लोग सब इस बात में सहमत हैं कि हमें एक नेशनल बुक पालिसी बनानी चाहिये सारे विषयों की किताबें और खासतौर से इतिहास की किताबें जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल कालेजों में पढ़ाई जाती हैं उनको नये ढंग से लिखा जाये। अब समय आ गया है जब कि हमें नेशनल इन्टीग्रेशन के ऊपर ध्यान देना होगा और हमारी एक यूनिफार्म पालिसी होनी चाहिये और एजूकेशन डिपार्टमेंट जो किताबें हमारे स्कूलों-कालेजों के लिए छापे वह एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा न करें बल्कि उनके अन्दर नेशनल इंटीग्रेशन की भावना पैदा करे। इस विषय की ओर मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान तीसरी दफा दिलाना चाहती हूं। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट जिसके द्वारा बच्चों के लिए किताबें छापी जाती है, पिछले साल नेहरू जी बर्थ एनिवर्सरी पर तीन मूर्ति हाउस में उसने एक बुक फैयर लगाया। मैं भी बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए वहां गई। चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट के स्टाल के अन्दर मैंने एक किताब उठाकर देखी जिसका टाइटल था 'दोज हू फाट फार फ्रीडम आफ कन्ट्री'। जब मैंने किताब खोली तो जहां सब बड़े बड़े नेताओं के नाम उसमें थे, गांधी जी का नाम था, नेहरू जी का नाम था, सरदार पटेल का नाम था वहां मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी था, लेकिन उसमें मौलाना आजाद का नाम नहीं था। मैं यह इसलिए नहीं कह रही हूं कि मौलाना आजाद का नाम हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने देश की आजादी में पूरा योगदान दिया है उनका नाम नहीं दिया गया है और जिन्होंने हिन्दुस्तान का बंटवारा कराया उनका नाम उसमें दिया गया है। उसमें उनकी ही लिस्ट दी जाय दोज हू फाट फार दि फ्रीडम आफ कन्ट्री। तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इसके बारे में कुछ निर्णय लेगी? जब पिछली बार मैंने यह बात उठाई थी तो उस समय चेयर पर श्री दिनेश गोस्वामी जी बैठे हुये थे और उन्होंने कहा था कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। तो मैं जानना चाहती हूं कि सरकार ने इस ओर क्या ध्यान दिया

और जैसा कि वर्मा जी ने बात उठाई है एक नेशनल पालिसी बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

SHRI P. K. THUNGON: Sir, this point was raised by the hon. Member on an earlier occasion also and I had assured her at that time that we would bring it to the notice of the Children's Book Trust of India. As regards the importance of having such a policy and having proper text books and university books, I entirely agree with the hon. Member that we should have a kind of constant effort to bring out proper books. At this stage. Sir, I would like to mention what we are doing in respect of book promotion. Sir, as you are aware, at tlie State level, we have text-book boards and those boards are looking after the work of bringing out proper text-books for our new generation, the school children. At the national level, the national apex body in this regard is the NCERT. Through the NCERT we are trying to evolve proper text-books so that proper education is imparted-to the students. Thirdly, in the case of text-books in universities, standard works are recommended according to the reuirements, according to the various stages of university education. And fourthly, to promote good books for higher learning, for universities particularly, we have collaboration with foreign countries also. We publish books.-.

SHRI JASWANT SINGH: You are confusing the whole thing.

SHRI P. K. THUNGON: I am trying to elucidate as to what we are doing at present in the case of book promotion and you are saying, I am confusing. You are not confused. I hope. *(Intermptijcms).* Sir, the UGC also provides assistance to encourage indigenous books in this regard. And these are certain steps we have taken at the primary Ievel., higher secondary level and university level for book promotion so that our young ' generation can get proper education.

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : इन्होंने मेरे सवाल का क्लेरीफिकेशन नहीं दिया । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी मोनिटेरिंग बाडी बनाई गई है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उनको देखती हो । अभी महाराष्ट्र के अन्दर क्रिश्चियन कम्यूनिटी के खिलाफ और मुस्लिम लोगों के बारे में, रिलीजन के बारे में, गलत लिखा गया था उस पर काफी एजीटेशन हुआ । यह पिछले साल की बात है । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी मोनिटेरिंग बाडी है जो यह काम करती हो और उन्होंने क्या स्टेप लिए हैं ?

SHRI P. K. THUNGON: The Book Trust is not directly under this Ministry. Therefore, I have already assured the honourable Member that we will take it up with them.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी शिक्षाविद का नाम बता रहे थे पुस्तक नीति में । मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं लेकिन जितना पढ़ा लिखा आदमी हूं तो इनमें से किसी का नाम जो तोता मैना की कहानी जैसी किताबें यहां बिकती रहती हैं वैसे लेखकों का नाम भी मैंने कभी नहीं पढ़ा । इन सब कोई लोगों ने किताब लिखी हैं या नहीं लिखी हैं । दूसरी बात मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय पुस्तक नीति का अर्थ यह है कि सरकार और उस सरकार के नौकरशाहों के जरिए ऐसी कमेटी बनाई जाये जो केवल अपने बच्चों की सुख सुविधा पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रख कर पुस्तक नीति तय करे पुस्तक के लेखन की बात करे और उनके द्वारा जो प्रकाशक लोग हैं उसको ख्याल में रखते हुए पुस्तक नीति तय करें और फिर उनके जो लेखक होते हैं जिनकी किताबों को

वे बच्चों के सिर पर लादना चाहते हैं, पढ़ाई कम और पीठ पर गधे जैसे बोझा लाद दो, ऐसे लेखकों की किताबों को बच्चों की पीठ पर लादने के लिए ऐसी कमेटी बनाते हैं तो क्या सरकार जो पुस्तक नीति बनाएगी उस पुस्तक नीति में यह भी होगा कि कागज सस्ता हो, छपाई सस्ती हो, जो भी पढ़ने वालों के हाथ में किताबें जायें उसके लेखक अच्छे हों, जिसको पढ़ने से उनको ज्ञान भी मिले। अभी माननीया सदस्या बोल रही थी वैसे मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। आज जिस देश के बच्चों के हाथ में गलत किताबें दी जा रही हैं उस कमेटी का निर्माण कौन करता है उस कमेटी को सुपरवाइज कौन करता है, इस कमेटी को सरकार बनाती है और सरकार के अफसर बनाते हैं। अगर इस तरह से कहीं पर गलती हुई हो तो उस के लिए न केवल सुधार होना चाहिये बल्कि इस तरह की किताबें लिखने वाले लोगों पर इस तरह की समिति को जो इस तरह के किताबों के प्रकाशन की अनुमति देती है दण्डनीय अपराध के तहत कार्यवाही होनी चाहिये। जो गलत शिक्षा देती है उस समिति को आप भंग कराइये। सरकार को चाहिये कि सभी समुदायों सभी वर्गों में जो माननीय शिक्षाविद हैं भारत की एक हस्ती हैं, ऐसे लोगों की कांफ्रेंस बुलावें उसमें तय करें कि देश की पुस्तक नीति क्या होगी, कैसी होगी, देश की शिक्षा नीति और प्रकाशन नीति कैसी होगी, मैं यह जानना चहता हूं कि क्या सरकार यह करने को तैयार है?

श्री पी० के० थुंगन : सदस्य महोदय को जो सन्देह है कि ऐसे लोगों को रखा गया है जो ठीक प्रकार से बच्चों के लिए पुस्तकें नहीं बना सकते हैं देश के लिए किताबें नहीं बना सकते हैं इस सन्देह को मैं इसलिए मिटाना चाहता हूं कि जो नाम मैंने यहां पढ़े हैं यह न केवल आफिशियल्ज हैं बल्कि इसमें न्यूजपेपर वाले भी हैं बुक पब्लिशर्ज और बुक सेलर्ज भी हैं, हर किस्म के . . . (**व्यवधान**)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : शिक्षाविद नहीं हैं।

श्री पी० के० थुंगन : शिक्षाविद भी हैं। बाकी जो दूसरा सुझाव उन्होंने दिया है मैं ख्याल में रखूंगा।

श्री सत्यपाल मलिक : माननीय सदस्य श्रीकान्त वर्मा जी से और हुक्मदेव जी से मैं सहमत हूं लेकिन मैं एक बात नयी आप से कहूंगा। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मौजूदा डर्टी शिक्षा मंत्रालय का और केन्द्र का, राज्यों का है उसके चलते पुस्तकों की जरूरत ही नहीं रह जायेगी। अब जो देश में पढ़ाई हो रही है वह पुस्तकों से नहीं हो रही है। पांच सैकड़ा लड़के टैक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ते हैं अच्छी किताबें नहीं पढ़ते हैं इतने बड़े पैमाने पर स्मगलिंग करके भी लोग इतने मालदार नहीं हुये जितने किताबें और कुन्जियां छाप कर पूरे देश में हुये हैं। छोटी-छोटी कुंजियां, देश में छप रहे हैं, वही लड़कों को दिये जाते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि उनको भी 10 सैकड़ा लड़के पढ़ते हैं 80--85 सैकड़ा लड़के गैस पेपर्स पढ़कर इम्तिहान में बैठते हैं। ऐसी दुःखद स्थिति सारे देश में शिक्षा की है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो आपने कमेटी बनाई है आप इसका टाइम लिमिट तय करें, दो महीने, तीन महीने लगातार ये लोग बैठें और इस बीच में पुस्तक नीति घोषित हो, एक साल में हम सारी पुस्तकें बदलवा दें और इसी के साथ सिलेबस और परीक्षा की प्रणाली में ऐसी तब्दीली करें जिससे गैस पेपर्स और कुंजियां खत्म हों तभी कुछ होगा इसके बिना यह सब फजूल का काम है। इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

SHRI P. K. THUNGON: So many other aspects are also involved in formulating such a book policy. Therefore, I would not be able to make any commitment. But I can assure the Hon'ble Member, as I have already stated, that I will convey the views and suggestions of the Hon'ble Members to the National Book Development Council and, as I have already stated, I will request them to form a group, if possible so as to accelerate the work

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Functioning of Sahitya Akademi

*83. SHRI M. BASAVARAJU: WiH the Minister of EDUCATION **AND** CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published under the head "Sahitya Akademi must be Scrapped" which appeared in the Illustrated Weekly of India, dated 13th-19th May, 1984 to the effect that extra literary reasons! fetched non genuine writers the Akademi awards and thus the' Akademi served no purpose;

(b) whether Government propose to streamline the working of the Sahitya Akademi; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. However, the factual inaccuracies have been correctly pointed in the letter of the Secretary, Sahitya Akademi, published in the Illustrated Weekly of India dated 24—30 June, 1984.

(b) and (c) The Sahitya Akademi which is an autonomous organisation, reviews constantly the Rules and Procedure governing the Awards.

Survey of Roads in Delhi

*86. SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Will'the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to make a survey of the conditions of roads in Delhi, particularly in the colonies; and

(b) if so, what steps Government propose to take to improve the roads?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b) A regular system for the maintenance and development of roads by the different agencies concerned in Delhi is already in operation.

@*86-A. (Transferred to the 2nd August, 1984).

Vocational studies in Delhi University

•87. SHRI J. K. JAIN: Will the-Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state:

(a) what are the arrangements in the Delhi University at present for providing vocational studies to students;

(b) whether it is a fact that a large number of students willing to take up vocational studies are denied admission to Colleges, Institutes on account of shortage of seats;

(c) whether Government propose to increase the number of seats in the existing vocational institutions and to open new institutions;" and

(©Previously Starred Question 6T transferred from the 26th July, 1984..